

प्रेषक,

रंजना,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,  
ननूरखेडा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक)

देहरादून: दिनांक: 23 सितम्बर, 2016

विषय: मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा सं०-1844/2015 के क्रियान्वयन हेतु  
धनराशि अवमुक्त करने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-नियोजन/5083/मु०मं०घो०/2016-17 दिनांक 01.06.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद अल्मोड़ा में की गयी घोषणा सं०-1844/2015 विधान सभा रानीखेत में गूजरगढ़ी प्राथमिक विद्यालय का नवनिर्माण किया जाएगा, के क्रियान्वयन हेतु अनुदान सं०-11 के अन्तर्गत पूंजीगत पक्ष में वर्ष 2016-17 हेतु की गयी बजट व्यवस्था में वित्त विभाग के शासनादेश सं०-359/XXVII(1)/2005 दिनांक 23.03.2015 में निहित प्राविधान के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पेयजल निगम रानीखेत द्वारा टी०ए०सी० कराने के उपरान्त अनुमोदित रू० 60.74 लाख की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में प्राविधानित बजट में अवशेष रू० 26.07 लाख (रुपये छब्बीस लाख सात हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन पर रखते हुए श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- (2) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किए जाय।
- (3) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखने हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- (4) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
- (5) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था रू० ला से उत्तरदायी होंगे।

- (6) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति कम आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायें।
- (7) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
- (8) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2006 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (9) कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण कराकर भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15.12.2008 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एमओयू अवश्य हस्ताक्षरित किया जाय। वर्णित कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही लागत से अधिक धनराशि किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगी।
- 03- उक्त से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अनुदान सं०-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01 सामान्य शिक्षा, 201-प्रारम्भिक शिक्षा, 03-प्राथमिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 04- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं०-86(P)/XXVII(3)/2016-17 दिनांक 16.9.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(रंजना)

अपर सचिव

सं० 934 (i)/XXIV(1)/2016-घो०-1844/2015 / तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी-1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. अपर सचिव, मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
04. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा
05. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा
06. मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा।
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. वित्त अनुभाग-5
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दन सिंह बिष्ट)

अनु सचिव